

Impact Factor - 6.261

ISSN - 2348-7143

INTERNATIONAL RESEARCH FELLOWS ASSOCIATION'S
RESEARCH JOURNEY

Multidisciplinary International E-Research Journal

PEER REFREED & INDEXED JOURNAL
September-2019 Special Issue - 197(B)

**Emerging Innovative Trends in Higher Education
An Interdisciplinary Approach**

Guest Editor :

Dr. M. N. Gaikwad

Principal

Gopikabai Sitaram Gawande Mahavidyalaya, Umardhed

Dist. Yavatmal (M.S) India

Executive Editor -

Dr. K. B. Shirse

Head, Dept. of History,

Gopikabai Sitaram Gawande Mahavidyalaya, Umardhed

Dist. Yavatmal (M.S) India

Associate Editors -

Prof. A. S. Joshi

Dr. V. R. Jiwatode

Dr. U. N. Patil

Dr. V. S. Ingle

Dr. K. D. Bompliar

Prof. S. S. Pachikudke

Chief Editor -

Dr. Dhanraj T. Dhangar (Yeola)



This Journal is Indexed in :

- Scientific Journal Impact Factor (SJIF)
- Cosmoc Impact Factor (CIF)
- Global Impact Factor (GIF)
- International Impact Factor Services (IIFS)

412

For Details Visit To : www.researchjourney.net

SWATIDHAN PUBLICATIONS

I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L
R
E
S
E
A
R
C
H
F
E
L
L
O
W
S
A
S
S
O
C
I
A
T
I
O
N



107	शेतकरी आत्महत्या : कारणे व उपाय	डॉ. रामकिशन चाटे	497
108	उच्च शिक्षणाचा पाया गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षण	श्री. अवधुत वानखेडे	501
109	सत्यशोधक पंढरीनाथ पाटील यांचे सामाजिक कार्य	डॉ. के. बी. शिरसे	506
110	विशेष गरजा असलेल्या बालकांच्या अधिकारात शिक्षणाची भूमिका	डॉ. जयश्री देशमुख	509
111	दारिद्र्याचे निर्धारकार व दारिद्र्याचे परिणाम	प्रा. कु. एस. एच. उजाडे	513
112	विश्वविद्यालयातील शैक्षणिक पद्धती	प्रा. क्रांती मुनेश्वर	519
113	शेतकरी आत्महत्या कारण आणि जबाबदारी	प्रा. पी. एन. संधारी	523
114	वऱ्हाडातील खिश्त्रन मिशनरीचे दलित चळवळीतील योगदानाचे विश्लेषण	डॉ. के. बी. शिरसे, डॉ. व्ही. एस. इंगळे, डॉ. आर. एच. बुटले	526
115	बहुजनांच्या सामाजिक शैक्षणिक प्रगतीत भाऊसाहेब डॉ. पंजाबराव देशमुखांचे योगदान	डॉ. के. बी. शिरसे, प्रा. एस. बी. वाघमारे, डॉ. व्ही. एस. इंगळे	529
116	मानवी मूल्ये आणि साहित्य	शिवाजी मोतीबोने	533
117	भारतीय अर्थव्यवस्थेत कृषीची भूमिका	प्रा. मिलिंद ढाले व डॉ. उषा पाटील	538
118	ग्राम जीवनाचे प्रत्ययकारी चित्रण करणारे लेखक : गणेश आवटे	प्रा. संध्या जंजाळ	541
119	पंचायतराज व्यवस्थेत महिला सहभाग व अडचणी	प्रा. राखी इंगळे	543
120	मानवी मूल्ये आणि साहित्य	डॉ. युवराज मानकर	547
121	वंचित घटक महिला सबलीकरणत शासनाची भूमिका	प्रा. ए. एम. काळबांडे	553
122	इतिहासाचे पुनर्लेखन आणि दृष्टीकोन	डॉ. संदिप डोंगरे	556
123	एकविसाव्या शतकात उच्चशिक्षणातील उभरत्या शिक्षण पद्धती	सुनिल थोरात	560
124	ग्रामीण महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षणाची सद्यस्थिती	प्रा. दत्तात्रय ढवारे	566
125	शिक्षणामध्ये मानवाधिकाराचे उपयोजन	प्रा. प्रमिला बोरकर	571
126	ग्रामीण शिक्षण : समस्या व सुधारणा	डॉ. सुनिल चकवे	575
127	बदलत्या शिक्षण पद्धतीमध्ये कुमारावस्थेतील विद्यार्थ्यांच्या अभ्याससवयी विकसनातील घटक	डॉ. विनय चव्हाण	579
128	इतिहास लेखनातील नवा विचार प्रवाह 'सबाल्टर्न इतिहास'	प्रा. सुरेंद्र बोरकर	583
129	विदर्भातील विशेष प्रश्न	प्रा. विजय गावंडे	586
130	भाषा आणि साहित्यातील नवे प्रवाह	डॉ. अनिलकुमार दडमल	691
131	पंढरीची वारी : एक अध्यात्मिक व सामाजिक चळवळ शोध व बोध	डॉ. हरिदास आखरे	695
132	उच्च शिक्षा की उत्पत्ती, विकास और बदलाव	डॉ. व्ही. बी. चांदजकर	698
133	महिला शिक्षा : आज की सामाजिक आवश्यकता	डॉ. भारती देशमुख	602
134	भारतीय इतिहास लेखन में सबाल्टर्नवादी विचारधारा	प्रा. वाय. एस. राजपूत	605
135	प्रशासन में नैतिकता	प्रा. एस. आर. सामृतवार	608
136	उर्दू साहित्य में नया रुझान	प्रा. मोहम्मद असरार	611
137	मानवाधिकारोंके अंमल में उच्च शिक्षा की भूमिका	प्रा. विजय गावंडे	614

Our Editors have reviewed papers with experts' committee, and they have checked the papers on their level best to stop furitive literature. Except it, the respective authors of the papers are responsible for originality of the papers and intensive thoughts in the papers. Nobody can republish these papers without pre-permission of the publisher.

- Chief & Executive Editor

413



उच्च शिक्षा की उत्पत्ती, विकास और बदलाव

प्रा. डॉ. व्ही. बी. चांदजकर
(राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख)

एम. एस. गोटे कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, वाशिम

उच्च शिक्षा का अर्थ :-

उच्च शिक्षा का अर्थ है सामान्य रूप से सबको दी जानेवाली शिक्षा के उपर किसी विशेष विषय या विषयी में विशेष, विशद तथा सुक्ष्म शिक्षा। यह शिक्षा के उस स्तर का नाम है जो विश्वविद्यालयों, व्यावसायिक विश्वविद्यालयों, कम्युनिटी महाविद्यालयों, लिरल आर्ट कॉलेज एवं प्रायोगिक संस्थानों आदि के द्वारा दी जाती है। प्राथमिक एवं माध्यमिक के बाद यह शिक्षा का तृतीय स्तर है। जो प्राय ऐच्छिक होते है। इसके अंतर्गत स्नातक एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण आदि आते है।

ऐसी शिक्षा का स्वरूप विशदता के साथ भारत वर्ष में प्रतिष्ठित हुआ था। उच्च शिक्षा देनेवाले भारतीय गुरुकुलों की बड़ी विशेषता यह थी की उनमें प्रारंभिक शिक्षा के लेकर उच्चतम शिक्षा शिष्याध्यापक प्रणाली से दी जाती थी। सबसे उपर के छात्र अपने से नीचे वर्ग के छात्रोंसे पढाते थे और अपने से नीचे वाले को यद्यपि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के पुत्र ही भर्ती के लिए जाते थे और वर्ण के अनुकूल ही बालकों को शिक्षा भी दी जाती थी। तथापी नित्यधर्म, स्वच्छता, शील और शिष्टाचार की शिक्षा प्रत्येक छात्र को दी जाती थी और प्रत्येक छात्र को गुरुकुल में रहकर आश्रम का समस्त कार्य स्वयं करना पडता था। कुछ गुरुकुल तो इतने बडे थे की वहाँ एक कुलपती, दससहस्र ऋषियों और ब्रह्मचारीयों का अन्य दानादि देकर उनको पढने का प्रबंध करते थे। छात्र भी अपने सामर्थ्य के अनुसार गुरुदक्षिणा देते थे। कोई भी राजा हो इन गुरुकुलों के प्रबंध में हस्तक्षेप नहीं करता था। इन गुरुकुलों का प्रारंभ वास्तव में उन परिषदों से हुआ जिनमें ४ से लेकर २९ तक विद्वान और मनीषी किसी नैमित्तिक, सामाजिक या धार्मिक समस्या पर व्यवस्था देने के लिए एकत्र होते थे। कुछ गुरुकुलों ने वर्तमान सावास विश्वविद्यालय रूप धारण कर लिया था। इन गुरुकुलों में वेद, वेदांग, दर्शन, नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि सभी विषयों को उच्चतम शिक्षा दी जाती थी और जब छात्र, सब विद्याओंमें पूर्ण निष्णात हो जाता था तभी वह स्नातक हो पाता था। ब्राह्मणों को यह छुट थी की वे चाहे तो जीवनभर विद्यार्जन करते रहे।

युरोप में मिस्त्री की सभ्यता सर्व प्राचिन मानी जाती है। किंतू वहाँ की उच्च शिक्षाप्रणाली का स्पष्ट विवरण नहीं मिलता। बाबल, मसुरिया के निवासियों तथा हिब्रू और फिनीसी लोगों में राजशास्त्र, नीतिशास्त्र, ज्योतिष और भूगोल की उच्च शिक्षा गिने चुने लोगों को ही दी जाती थी। भूतान में सौंदर्य की उदात्त भावना के साथ व्याकरण, काव्य, भाषा, शैली, अलंकारशास्त्र, संगीत, गणित, भौतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र और राजनीति की शिक्षा दी जाती थी। एक एक व्यक्ती विषय पंडित था। उसी के पास युवक को शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाना पडता था। स्पार्टा के लोगों को केवल युद्ध की ही शिक्षा मिली, अन्य विषयों का पूर्ण अभाव रहा। वास्तव में एथेन्स ही युनानी उच्च शिक्षा का विद्यानगर था। जहाँ सुकरात, जेनोफन, अरस्तू जैसे विद्वान शिक्षाशास्त्री और दार्शनिक विद्यमान थे। जब रोमवालों ने यूनान का यह प्रभाव पडा की वहाँ भी इतिहास, विज्ञान दर्शन की उच्चशिक्षा दी जाने लगी जिसके प्रभाव से सिसरो, सैनेको जैसे शिक्षणशास्त्री और वक्ता

414



उत्पन्न हुए। तथा कुछ ही समय में उच्च शिक्षा के अनेक विद्यालय भी खुल गये किंतु रोम साम्राज्य के छिन्न भिन्न होने साथ ही यूनान और रोम की संपूर्ण शिक्षा पध्दती समाप्त हो गई।

इसाई मठों में पहले धर्मनिरपेक्ष और प्रार्थना के साथ पढ़ना, लिखना, गाना, पूजा करना और गणित की शिक्षा दी जाती थी किंतु इसके पश्चात वहाँ विद्यालयी को मिलाकर सात ज्ञान विस्तारक कलामो के शिक्षणक्रम चला और तभी से इन शास्त्रों के लिए शब्द का प्रयोग चल पडा जो अजकल भ्रामक रूप से हमारे विश्वविद्यालयों की उपाधि प्रयुक्त हो रहा है। युरोप में प्रारंभ में कुछ विद्यार्थी किसी विशेष विद्या के आचार्य के पास अध्ययन के लिए सालेरनो में भेषज्यविद्या के लिए या बोलोना में न्यायनीति शिखने के लिए। इस प्रकार दक्षिण युरोप में बोलोना के आदर्श पर विश्वविद्यालय खुले और उत्तर में पेरिस के आदर्श पर। इनके अतिरिक्त एक शिक्षणाचार्य का प्रमाणपत्र भी था। जो शिक्षक होने के अनुज्ञापत्र समझा जात था। धीरे धीरे विश्वविद्यालयों ने वर्तमान रूप धारण किया। इनमें उच्चतम शिक्षा का अर्थ है हाई स्कूल के पश्चात महाविद्यालयों या व्यावसायिक संस्थाओं कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, कला महाविद्यालय, संगीत महाविद्यालय में दी जानेवाली शिक्षा जिसके लिए विश्वविद्यालय से उपाधि या राजकीय विभागों की और से परीक्षा लेकर प्रमाणपत्र दिये जाते है। उच्च शिक्षा देने का अधिकांश कार्य विश्वविद्यालय ही करता है।

भारत का उच्च शिक्षा तंत्र :-

भारत का उच्च शिक्षा तंत्र अमेरिका, चीन के बाद विश्व का सबसे बड़ा उच्च शिक्षा तंत्र है। विगत ५० वर्ष में देश के विश्वविद्यालय संख्या में ११.६ गुना, महाविद्यालय में १२.५ गुना विद्यार्थी संख्या ६० गुना, महाविद्यालयों में शिक्षकों की संख्या में २५ गुना वृद्धि हुई है। सभी को उच्च शिक्षा के समान अवसर सुलभ कराने की नीति के अंतर्गत संपूर्ण देश में महाविद्यालयों की संख्या उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और साथ ही उच्च शिक्षा की अस्थापना सुविधा पर विनियोग भी तदनुरूप बढ़ा है।

महत्व :-

उच्च शिक्षा पाने के बाद व्यक्ति बुद्धिजीवी बन जाता है और समाज में योगदान दे पाता है। उच्च शिक्षा पाने से व्यक्ति की सोच का दायरा बढ़ता है। वह दूर दृष्टी प्राप्त कर पाता है। इसके साथ ही वह देश रास्ते पर लाया जा सके। उच्च शिक्षा पाने से महिलाएं सशक्त होती है। वे दूसरी महिलाएं के लिए प्रेरणा बनती है। इसके साथ ही दूसरी महिलाओं को रोजगार देकर बेरोजगारी की समस्या को दूर करती है। उच्च शिक्षा पाने के बाद महिलाओं का स्तर साधारण महिलाओं से अधिक बढ़ जाता है। वह अच्छे बुरे में फर्क कर पाती है। इस बारे में जॉर्ज वॉशिंगटन करवर ने कहीं की शिक्षा स्वतंत्रता के स्वर्ण द्वार खोलने की कुंजी है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पिछले पांच दशकों में देश में उच्च शिक्षा का क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। स्वतंत्रता पूर्व देश में मात्र तीन विश्वविद्यालय थे। वही अब उनकी संख्या २५० के आसपास पहुंच चुकी है।

उच्च शिक्षा के निर्मित समर्पित इन संस्थानों में १२ भाषाओं विज्ञान, कला, वाणिज्य, चिकित्सा सहित शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनेक व्यावसायिक महत्व के पाठ्यक्रमों की शिक्षा की व्यवस्था है। इन संस्थानों में प्रतिवर्ष लगभग ७५ लाख विद्यार्थी प्रवेश पाते है। फिर भी कई युवक युवतीयां उच्च शिक्षा से वंचित रह जाती है। अतः अभी काफी संख्या में नए संस्थानों को स्थापित करने की आवश्यकता है।



उच्च शिक्षा में बदलाव :-

आज के समय के साथ उच्च शिक्षा को बदलने की एक बहस ही छिड़ गई है। इस बदलाव तथा अनेक संस्थानों की स्थापना के लिए सरकार को एक बहुत बड़ी पुंजी है की आवश्यकता है। जो वर्तमान समय में संभव हो नहीं दिखता।

अतः उच्च शिक्षा का निजीकरण ही एक दुसरा विकल्प बचता है। यदि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और उसकी व्यावहारिकता विचार किया जाए तो वर्तमान शिक्षाप्रणाली शिक्षित बेरोजगारी की बहुत कड़ी संख्या प्रत्येक वर्ष तैयार करती जा रही है।

प्रतिवर्ष 2-4 लाख बेरोजगार के नाम रोजगार कार्यालय दर्ज हो रहे हैं। इसके अलावा बहुत ऐसे भी बेरोजगार होते हैं। जो इन कार्यालय में अपना नाम दर्ज ही नहीं करते। रोजगार के अवसर नहीं होने के कारण कई युवक दिशाहीन होकर गैर कानूनी काम और उन्मुख हो रहे हैं।

सरकारद्वारा उच्च शिक्षापर किए जा रहे व्यय की और देखा जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है की सरकार का अधिक ध्यान देश की जनसंख्या को शिक्षित करने अथवा प्राथमिक शिक्षापर ही अधिक केंद्रित है। उच्च शिक्षा के लिए उच्च संसाधनों की कमी हमेशा से बनी रही है। चौथी पंचवर्षिक योजना के बाद से उच्च शिक्षापर भारी कटौती की जा रही है। चौथी योजना के दौरान उच्च शिक्षा पर कुल शिक्षा व्यय का 25 प्रतिशत भाग खर्च किया गया, वहीं अब नौवीं योजना में मात्र 92 प्रतिशत रह गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से प्रारंभ से शिक्षा में निजीकरण के प्रवेश का संकेत मिलने लगा। इस नीति में उच्च शिक्षा संस्थानों का बेहतर रूप से संचालित करने के लिए चन्दा एकटूठा करना तथा इमारतों के रख रखाव एवं रोजमर्रा के काम में आनेवाली वस्तुओं की पूर्ति में स्थानिय लोगों की सहायता की बात कही गई।

इस बीच विश्व बैंकद्वारा विकसनशील देशों में शिक्षा के खर्च के पैटर्न पर एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें सलाह दी गई की आर्थिक संसाधनों की कमी को देखते हुए शिक्षापर आनेवाला खर्च का एक बड़ा हिस्सा अभिभावकों पर डाला जाए। वर्ष 1999 में डॉचगल समायोजन के अंतर्गत नरसिम्हाराव सरकारने आर्थिक उदारकरण को आगे बढ़ाया जिसमें स्पष्ट हो गया कि उच्च शिक्षा को विश्व बैंक के मुद्रावों के अनुरूप डाला जाएगा।

उसी दौरान खड़ी संकट की आड़ में उच्च शिक्षा के बजट में यु. जी. सी. द्वारा 35 प्रतिशत की कटौती कि गई। तथा विश्वविद्यालय को निर्देश दिया गया की वे अपने संसाधन स्वयं जुटाने का प्रयास करें। केंद्र सरकार के निर्देशपर यु. जी. सी. ने 1992 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमुर्ती के पुनीया की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिती का गठन किया गया था। हा समिती का उद्देश भारतीय विश्वविद्यालयों उगाही के संबंध में सुझाव देना था।

इस समितीने 1993 में अपनी रिपोर्ट यु.जी. सी. को सौंपी। इस रिपोर्ट में उच्च शिक्षा की निजीकरण के पक्ष में मत व्यक्त किया गया था। केंद्रीय विश्वविद्यालय में फिस्त ढांचे की समीक्षा और सुधार संबंध में नटिल आनंद कृष्णन समिती की सिफारिशों से भी स्पष्ट हो गया की अब उच्च शिक्षा का खर्च अभिभावकों पर डालने की तैयारी हो चुकी है।

इन सारी समितीयों की रिपोर्ट का सार यही है की उच्च शिक्षा पर खर्च वर्तमान आर्थिक परिप्रेक्ष में किमती राष्ट्रीय संसाधनों का उपभोग है। इस प्रकार अब एक ही विकल्प बचा की निजी क्षेत्र के लिए उच्च



शिक्षा के दरवाजे खोल दिय जाय ताकि सरकार के पीछे हटने से होनेवाली क्षति की भरपाई हो सके।
"पोलिसी फ्रमवर्क फॉर रिमाक्स इन एज्यूकेशन" नाम से २४ एप्रिल २००१ की मुकेश अम्बानी तथा कुमार मंगलम द्वारा व्यापार और उद्योग गठित प्रधानमंत्री की सलाहकार परिषद को उच्च शिक्षा पर एक रिपोर्ट सौंपी गई। रिपोर्ट के मुताबिक इसे २०१५ के भारत की शैक्षणिक आवश्यकताओं की ध्यान में रखकर तयार किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार २०१५ तक उच्च शिक्षा पर ४२ हजार करोड रूपय खर्च होंगे। इसके अतिरिक्त भारत सरकार को १५ नए संस्थानों के निर्माण में ११ हजार करोड की पूंजी लगानी पड़ेगी।

सारांश :-

सरकार के लिए केवल अपने बल पर इतनी पूंजी लगाना सम्भव नहीं है। इसलीय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी और सरकारी क्षेत्र में क्रमशः ४० और ६० प्रतिशत निवेश की संस्तुति की गई है। इससे उच्च शिक्षा निश्चित तौर पर बरफ़ी महेंगी हो जाएगी और यह केवल धनाढ्य वर्गोंतक के बच्चों के लिए ही सीमित होकर रह जाएगी।

संदर्भ:-

1. Committees & Commission in India, 1947-73 Page- 57
2. Current Trends In Higer Education, J. Mohanty, Page- 82
3. Introduction Of New Subject In Higer Education; Need Of Time, Mr. Anand Yashwant Raikwad, 2018 Page 7
4. Higer Education Through Tevelevision; The Indian Express, 2000. Page 37
5. National Education Policy Need More Extensive Reforms To Succeed, Financial Express, 13 Aug. 2019
6. Varsities To Write To UGC, The Hindu, 2 Aug. 2019